



सूत्र सेवा बसों को जबरन रोका

स्टाफ़-यात्रियों से मारपीट का आरोप, बहुआ गांव के पास बुधवार दोपहर की घटना

नवभारत न्यूज भिण्ड, 4 फरवरी। मेहगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुआ मोड़ पर बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ग्रामीणों के एक समूह ने भिंड-ग्वालियर रूट पर संचालित सूत्र सेवा की नॉनस्टॉप बसों को जबरन रोक लिया। ग्रामीण हर गांव में बस स्टॉप देने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि विरोध करने पर बस चालक-कंडक्टर और यात्रियों के साथ मारपीट की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया।

नॉनस्टॉप बस को बहुआ मोड़ पर रोका:जानकारी के अनुसार, सूत्र सेवा की 719 नंबर बस ग्वालियर से भिंड की ओर आ रही थी। इसी दौरान बहुआ मोड़ पर पहले से मौजूद 20 से 25 ग्रामीणों ने बस को जबरन रोक लिया। ग्रामीणों ने चालक और कंडक्टर से बहुआ गांव सहित आसपास के सभी गांवों में बस रोकने की मांग की।

चालक-कंडक्टर और यात्रियों से की मारपीट:प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मांग पूरी



न होने पर ग्रामीणों ने गाली-गलौज करते हुए चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब बस में सवार यात्रियों ने बीच-बचाव किया तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की गई। बस में चीख-पुकार मच गई और कई यात्री डर के कारण बस से उतरकर इधर-उधर भागने लगे।

पांच बसें दो घंटे तक रोकी, यातायात प्रभावित:ग्रामीणों की दबंगई यहीं नहीं रुकी। भिंड से ग्वालियर की ओर जाने वाली सूत्र सेवा का अन्य बसों को भी रास्ते में रोक लिया गया। कुल पांच बसें करीब दो घंटे तक मौके पर खड़ी रहीं, जिससे सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

तीन लोग हिरासत में:भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भीड़ को नियंत्रित किया गया।

पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पृच्छाछ शुरू कर दी। इसके बाद बसों को आगे के लिए रवाना किया गया। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है।

बस मैनैजर ने लगाए गंभीर आरोप:सूत्र सेवा बस के मैनैजर पप्पू शर्मा ने बताया कि नॉनस्टॉप परमिट पर चलने वाली बसों को जबरन रोका गया और स्टाफ व यात्रियों के साथ मारपीट की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी ग्रामीणों ने पथराव किया, लेकिन अब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।**मास्टरमाइंड पर कार्रवाई की मांग:**बस मैनैजर ने बहुआ गांव निवासी दीपू दंडोतिया को पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों को समझाई दी

ग्रामीणों ने सूत्र सेवा बसों को बहुआ मोड़ पर रोका था, हमने लोगों को समझाई दी। जिसके बाद उन लोगों ने बसों को छोड़ दिया।**महेश शर्मा, टीआई, थाना मेहगांव।**

गेहूं उपार्जन के लिये 7 से शुरु होगा पंजीयन

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 4 फरवरी. रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये किसान पंजीयन 7 फरवरी से शुरू होगा. किसान 7 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं.

पंजीयन के लिए कुल 3186 पंजीयन केन्द्र बनाये गए हैं. केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये गेहूं का एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रुपये अधिक है. पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है.



नवभारत न्यूज भिण्ड, 4 फरवरी। रेल कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को आधार से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को झांसी रेल मंडल में आधार नामांकन एवं अपडेशन शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभा कक्ष (द्वितीय) में किया। यह शिविर यूआईडीएआई द्वारा अधिकृत डाक विभाग के सहयोग से कार्मिक विभाग के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। शिविर में रेल कर्मचारी,

रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवजन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपने आधार कार्ड में आवश्यक संशोधन कराने के साथ-साथ नए आधार नामांकन की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। शिविर के शुभारंभ अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने स्वयं अपने आधार कार्ड में सुधार कराकर कर्मचारियों को इस पहल के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आधार आज एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज बन चुका है और इसमें सही एवं अद्यतन जानकारी होना बेहद आवश्यक है, जिससे विभिन्न सरकारी और विभागीय सेवाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके। डीआरएम ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि वे स्वयं, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवारजन इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि कार्यालय परिसर में ही यह सुविधा

प्रदूषित जल के शोधन के लिए परिसर में लगाए ई.टी.पी.



औद्योगिक संवर्धन एवं औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के संबंध में बैठक

नवभारत न्यूज मालनपुर, 4 फरवरी। कलेक्टर भिण्ड का अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन मालनपुर में औद्योगिक संवर्धन एवं औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर भिण्ड द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं संबंधितों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। 06 फरवरी को इंडियन ऑयल बॉटलिंग प्लांट में औद्योगिक सुरक्षा आधारित मॉक ड्रिल रखी गई है, जिसमें औद्योगिक इकाइयों द्वारा भाग लिया जाये, फायर

इकाइयों में कर्मचारियों के परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी बस की सेवायें उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाये। बैठक में (कार्य .एमपीआईडीसी) अनीषा श्रीवास्तव, महाप्रबंधक अमित कुमार शर्मा, एसडीएम गोहद राजन नाडिया, नायब तहसीलदार राकेश श्रीवास्तव, सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आनंद राय सरदार, पुलिस फायर स्टेशन प्रभारी निरीक्षक सतीश चतुर्वेदी तथा औद्योगिक इकाइयों के आदित्य शुक्ला (नोवा) मुकुल चतुर्वेदी (सूर्या रोशनी), अभिषेक प्रियदर्शी (गोदरेज), संतोष पाठक एसआरएफ), सुधीर नन्दा (आईओसी), अन्य विभागों के अधिकारी एवं औद्योगिक क्षेत्र की वृहद एवं मध्यम इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

घने कोहरे से उड़ानें प्रभावित

मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण इंदौर एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित रहा. दृश्यता घटकर 600 मीटर तक पहुंचने से इंदौर आने वाले दो यात्री विमान यहां लैंड नहीं कर पाए और उन्हें क्रमशः अहमदाबाद और राजकोट भेजा गया. इसके कारण यात्रियों को संबंधित शहरों में ही इंतजार करना पड़ा.



यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज का दंडवत प्रदर्शन

भिंड। फूप कस्बे में बुधवार को यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज के युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए दंडवत करते हुए रैली निकाली, जिसमें पूरे क्षेत्र का ध्यान खींच लिया। आंदोलनकारियों ने इस कानून को सवर्ण समाज के सामाजिक और शैक्षणिक हितों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। सवर्ण समाज के युवाओं ने कस्बे के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली। रैली के दौरान युवा सड़क पर लेटकर दंडवत करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर एकत्र हो गए। रैली के चलते कुछ देर के लिए कस्बे के मुख्य मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा।

रेत खदान पर हथियारों के दम पर अवैध उत्खनन , किसानों में दहशत



नवभारत न्यूज भिण्ड, 4 फरवरी। अमायन थाना क्षेत्र अंतर्गत बरेठी खुर्द रेत खदान में अवैध उत्खनन का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि रेत माफिया हथियारों के बल पर खेतों की जमीन और मरघट की भूमि से खुलेआम रेत निकाल रहे हैं, जबकि विरोध करने वालों को डराया-धमकाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। एक महिला किसान ने आरोप लगाया कि जब उसने रेत चोरी का विरोध किया तो माफियाओं ने उसे खुलेआम धमकाया। हालात ऐसे हैं कि कई किसान कैमरे पर बयान देने से भी डर रहे हैं।



नवभारत न्यूज भिण्ड, 4 फरवरी। अंदेर थाना क्षेत्र में फायरिंग

जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें ट्रैक्टरों के जरिए रेत का अवैध परिवहन साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी खनिज विभाग की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सबूत वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के रूप में मौजूद हैं, तब भी विभाग की निष्क्रियता सवाल खड़े करती है।

सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी नहीं रुका खनन:किसानों ने बताया कि उन्होंने अवैध खनन की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत के बाद भी रेत उत्खनन और परिवहन लगातार जारी है। इससे ग्रामीणों को लगने लगा है कि प्रशासनिक स्तर पर मामले को गंभीरता से नहीं

लिया जा रहा है। लगातार बढ़ते मामलों के बीच ग्रामीणों का आक्रोश अब खनिज विभाग के अधिकारियों पर भी फूट पड़ा है। कई किसानों ने रेत माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं।**ग्रामीणों की प्रमुख मांगें:** ग्रामीणों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। अवैध उत्खनन में शामिल रेत माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हो। यदि किसी अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है तो उस पर भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वायरल वीडियो और ऑडियो सामने आने के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक की कार्रवाई सवालों के घेरे में बनी हुई है। पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

भाजपा कार्यालय में आजीवन सहयोग निधि को लेकर बैठक



नवभारत न्यूज भिण्ड, 4 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्धारित संगठनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत पार्टी जिला कार्यालय पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में आजीवन सहयोग निधि की तैयारी एवं लक्ष्य पूर्ति को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया कि 10 फरवरी तक सभी रसीद पत्रक जमा कर दिए

जाएं, ताकि जिले को दिया गया लक्ष्य प्रदेश नेतृत्व की मंशा के अनुरूप समय पर पूरा किया जा सके।

बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह नरवरिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसका संचालन कार्यकर्ताओं के समर्पण, निष्ठा और सहयोग से ही होता है।

उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि ‘समर्पण दिवस’ के अवसर पर आजीवन सहयोग निधि का लक्ष्य पूर्ण करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।**हर बुथ से होगी आजीवन सहयोग निधि की शुरुआत:** जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिले के सभी 29 मंडलों में कार्यकर्ता प्रत्येक बुथ पर पहुंचकर पार्टी की विचारधारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं और सहयोग राशि के लिए आग्रह करें। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यह उपलब्धि कार्यकर्ताओं के परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। इसी अवसर पर उन्होंने प्रदेश से प्राप्त रसीद बुक मंडल अध्यक्षों को

सौंपी। बैठक का शुभारंभ भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। संचालन जिला महामंत्री मनोज अनंत ने किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष सज्जन सिंह यादव, जिला मंत्री बजरंग सिंह भदौरिया, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह ठीपू, भदौरिया प्रिंस, दुबे राय सिंह नरवरिया, रोहित करैया, विनोद नजैन, रवि शर्मा, उदय सिंह कुशवाहा, जले सिंह नरवरिया, मौनू नरवरिया, मनोज सिंह कुशवाहा, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष पिंकी सागर, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अतिराज सिंह नरवरिया सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

कैबिनेट ने लिया निर्णय

25 602 परिवारों को मिले पट्टों की होगी रजिस्ट्री

06 सौ करोड़ से अधिक खर्च करेगी राज्य सरकार

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 4 फरवरी. राज्य सरकार सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापित परिवारों को मिले आवासीय पट्टों का अब अपने खर्च पर रजिस्ट्री कराएंगी. ऐसे लगभग 25602 परिवारों को मिले पट्टे की रजिस्ट्री कराने पर राज्य सरकार 600 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी. इन में से ज्यादातर परिवार जनजातीय समुदाय से हैं.

उन्हें परियोजना के कारण वर्ष 2016 में विस्थापित किया गया था, अब 9 वर्ष बाद रजिस्ट्री कराने से वे अपने आवास के पूर्ण स्वामी बन जाएंगे. रजिस्ट्री के लिए



चलती रहेंगी संबल सहित 10 योजनाएं

कैबिनेट ने 6 विभागों की 10 योजनाओं की वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक निरंतरता के लिए 15,009 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है. निर्णय के मुताबिक वित्त विभाग की लोक वित्त पोषित 500 करोड़ से कम की 8 योजनाओं के लिए 115 करोड़ 6 लाख रुपये, श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल 2.0 योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपये, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना और स्थापना एवं कार्यालयीन योजनाओं के लिए 3 हजार 376 करोड़ 66 लाख रुपये, पशु पालन एवं डेयरी विभाग की डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ब्लॉकग्रांट योजना एवं पशुपालन, पशु विकास और गौ संवर्धन योजना के लिए 6 हजार 472 करोड़ 18 लाख रुपये, महिला एवं बाल विकास की किशोर कल्याण निधि योजना और घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना के लिए 24 करोड़ 70 लाख रुपये और पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कल्याण की अल्पसंख्यक स्वरोजगार/उद्यम योजना के लिए 21 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है. कैबिनेट ने मध्य राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग कर कर्मचारियों का संविलयन महिला बाल विकास विभाग में करने की स्वीकृति दे दी है. बोर्ड में 6 कर्मचारी पदस्थ थे.

सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के पट्टों की रजिस्ट्री कराएगी सरकार

पंजीयन शुल्क और स्टॉम्प ड्यूटी की भरपाई करने की जिम्मेदारी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की होगी.

कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट ने मैहर एवं कटनी जिलें में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 620 करोड़ 65 लाख रुपये की भी मंजूरी दी है. मैहर एवं कटनी की धनवाही सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना लागत 53 करोड़ 73 लाख रूपए है, इससे 3500 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और मैहर एवं कटनी जिले के 9 ग्राम के 2810 किसानों को फायदा होगा. इसी तरह कटनी जिले की बरही सूक्ष्म उद्दहन सिंचाई परियोजना लागत 566 करोड़ 92 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इससे, कटनी जिले की बरही एवं विजयराघवगढ़ तहसील के 27 ग्राम के 11,500 किसान लाभान्वित होंगे और 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी. दोनों ही परियोजना से 14310 किसानों को फायदा मिलेगा.

ओला-पाला वाले क्षेत्रों में सर्वे के निर्देश

- ▶ अनौपचारिक कैबिनेट में सीएम ने कहा
- ▶ प्रदेश के सभी अंचलों में कृषि कैबिनेट होगी

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 4 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जहां-जहां भी ओला-पाला से फसलें प्रभावित हुई हैं, उन जिलों के कलेक्टरों, सर्वे काराकर तत्काल सहायता राशि किसानों को उपलब्ध कराएं. किसानों के सभी प्रकार के हित सुनिश्चित करने और उनकी आय दोगुना करने के उद्देश्य से ही वर्ष-2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है.

कृषक कल्याण कृषि वर्ष में मालवा, निमाड़, चंबल और विन्ध्य अंचलों में कृषि कैबिनेट आयोजित की जाएगी. कृषि के साथ उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां अपनाने के लिए कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट से पहले अनौपचारिक



कैबिनेट में मंत्रियों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने हाल के कार्यक्रमों की जायकारी साझा की. उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया. पुष्प उत्पादन और देश-विदेश में फूलों की बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा.

प्रदेश में नरवाई प्रबंधन और

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में राज्य स्तरीय एमपी यूथ गेम्स-2026 के भव्य आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रतिष्ठित आयोजनों में देशज खेलों को भी शामिल किया जाए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीवा मेडिकल कॉलेज में 750 बेड की क्षमता वृद्धि की गई है. प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीपशुपतिनाथ लोक में विकसित की गई सुविधाओं और प्रतिमा के क्षरण को रोकने के लिए किए गए उपाय को अनुकरणीय बताया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में केंद्रीय बजट की विशेषताओं से जनसामान्य को अवगत कराने के निर्देश दिए.